



कोटा

Rashtradoot

फोन:- 2386031, 2386032 फैक्स:- 0744-2386033

वर्ष: 51 संख्या: 103

प्रभात

कोटा, रविवार 25 जनवरी, 2026

कोटा/24/2012-14

पृष्ठ 8

मूल्य 2.50 रु.

# राहुल भी उस सुविधा के आरामदेह जाल में फंस गये हैं, जिसमें सोनिया गांधी फंसी थीं

सोनिया गांधी सदा इस बात से बचती थीं , कि पार्टी अपनी हार के कारणों पर गंभीरता से बहस करे, और यह तय हो कि, हार के लिये जिम्मेवार कौन था

जो मुद्दे हैं उन्हें पार्टी नेतृत्व के साथ उठाना है

## वंदे मातरम के दौरान भी सीधे खड़ा होना पड़ेगा

केन्द्र सरकार राष्ट्र गीत वंदे मातरम को राष्ट्र गान जन गण मन जैसा दर्जा देने की तैयारी में है

- श्रीनंद झा -  
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -  
नई दिल्ली, 24 जनवरी। क्या भारत के राष्ट्र गीत को राष्ट्रीय गान के समान दर्जा और सम्मान मिलना चाहिए?

इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्” को राष्ट्र गान के समान सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक विधिवत प्रस्ताव तैयार करना था। वर्तमान समय में, दोनों गीतों के लिए कानूनी और अनिवार्य प्रोटोकॉल में एक महत्वपूर्ण अंतर मौजूद है। उदाहरण के लिए, जब राष्ट्र गान बजाया जाता है तो खड़ा होना अनिवार्य है और ऐसा न करने या इनकार करने पर “प्रीवेन्शन ऑफ इन्सल्ट्स नैशनल ऑनर एक्ट, 1971” के तहत दंड का प्रावधान है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय गीत के बजने पर खड़ा होना अनिवार्य बनाने वाला कोई लिखित नियम या कानूनी बाध्यता फिलहाल मौजूद नहीं है।

वंदे मातरम् पर भाजपा सरकार का नया जोर आगामी विधानसभा चुनावों, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, हिंदू मतों के एकीकरण की पार्टी की राजनीतिक रणनीति के अनुरूप देखा जा रहा है। इस गीत को लेकर ऐतिहासिक, धार्मिक और

■ राष्ट्र गान जन गण मन जब बजाया जा रहा हो तब खड़े होना अनिवार्य है और इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नैशनल ऑनर एक्ट बनाया गया है, पर वंदे मातरम में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। केन्द्र सरकार वंदे मातरम को भी राष्ट्र गान, जन गण मन जैसा दर्जा देने की तैयारी में है।

■ इस सम्बध में गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। चर्चा है कि भाजपा सरकार बंगाल चुनावों के मद्देनजर वंदे मातरम के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है और इस आधार पर वोटों के धुवीकरण की उम्मीद कर रही है।

राजनीतिक व्याख्याओं से जुड़े विवाद लंबे समय से रहे हैं। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत उनके उपन्यास “आनंद मठ” से लिया गया है और इसमें कुल छह अंतरे (स्टैन्जा) हैं, जिनमें हिंदू देवी की छवियां शामिल हैं। पार्टी के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस कार्यसमिति ने 1937 की बैठक में केवल पहले दो अंतरों के प्रयोग का निर्णय लिया था, क्योंकि बाद के अंतरे मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को अलग-थलग कर सकते थे।

यह विवाद पिछले वर्ष गीत की 150वीं वर्षगांठ पर फिर से उभरा, जब

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तर्क दिया कि कांग्रेस द्वारा गीत को संक्षिप्त किए जाने का देश के विभाजन में योगदान रहा। कांग्रेस ने इस निर्णय का बचाव करते हुए इसे सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम बताया। कुछ मुस्लिम विद्वानों, जैसे मौलाना अरशद मदनी, ने कहा है कि वे राष्ट्रीय गीत का सम्मान करते हैं, लेकिन, एक्शरवाद से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के कारण, इसके सामूहिक गायन में भाग नहीं ले सकते।

1905-08 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान “वंदे मातरम्” एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## पुरानों पर संदेह है और नयों पर भरोसा नहीं हो रहा

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेना के उच्च पदों पर तैनात अपने पुराने साथियों को हटा रहे हैं, पर उनकी जगह नई नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं

थरुर ने कैनडा के प्र.मंत्री की चेतावनी का समर्थन किया

- जाल खंबाता -  
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -  
नई दिल्ली, 24 जनवरी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को सुझाव दिया कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में भारत को कैनडा के प्रधानमंत्री की ‘जीवित बने

■ थरूर ने कहा, आज विश्व की व्यवस्था जिसकी लाठी उसकी भैंस पर आधारित है, नियम टूटते जा रहे हैं। भारत को भी कैनडा के प्र.मंत्री की चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए।

रहने’ की अपील से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, इस सप्ताह दावोस की बर्फीली पृष्ठभूमि में कैनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऐसा भाषण (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

■ हाल ही में शी ने अपने पुराने साथी और बेहद वफादार रहे जनरल झांग को पद से हटा दिया, वे चीन के सर्वशक्तिमान सैंट्रल मिलिटरी कमिशन के वाइस चेयरमैन थे।

■ जनरल झांग और शी की राजनैतिक व सामाजिक पृष्ठभूमि एक जैसी थी इसीलिए जनरल झांग शी के बेहद विश्वासपात्र बन गए। लेकिन शी ने भ्रष्टाचार के संदेह में जनरल झांग को हटा दिया है।

■ असल में शी ज़िनपिंग ने चीन की सेना का शुद्धिकरण शुरू किया है, क्योंकि, भारी भ्रष्टाचार की खबरें मिल रही थीं पर इससे सेना के उच्चस्तर पर एक खालीपन सा आ गया है।

सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। लगातार चल रही इन कार्रवाहियों में कई शीर्ष

सैन्य कमांडरों को पद से हटाकर जेल या हिरासत शिविरों में भेजा गया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## ट्रम्प के “गाज़ा स्ट्रिप प्लान” ने देश के पुराने अमेरिका - इज़रायल विशेष सम्बंधों को खतरे में डाल दिया है?

कतर व टर्की को अमेरिका उस बोर्ड का सदस्य बनाने को आमदा है, जो “गाज़ा-स्ट्रिप” का पुनर्निर्माण करेगा। पर, इज़रायल इनकी सदस्यता किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

-सुकुमार साह-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 24 जनवरी। वॉशिंगटन और यरुशलम के बीच तनाव अब खुलकर सामने आ गया है। इज़रायल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्धोत्तर गाज़ा के लिए वाइट हाउस द्वारा प्रस्तावित बोर्ड को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया है, लेकिन अमेरिका इज़रायल की आपत्तियों के बावजूद इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है। जो मामला पहले कूटनीतिक बैकचैनलों के ज़रिये चुपचाप सुलझाया जा सकता था, वह अब लंबे समय से सहयोगी रहे दो देशों के बीच एक दुर्लभ सार्वजनिक टकराव में बदल गया है। इससे न केवल अमेरिका-इज़रायल संबंधों को गहरी

■ इज़रायल का सोच है कि कतर के “हमास” से अच्छे सम्बंध हैं, और टर्की के राष्ट्रपति एरडोगन, इस समय इज़रायल व प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रबलतम आलोचक हैं, टर्की को इस्लामिक देशों का नेता बनाने के प्रयास में हैं।

■ इज़रायल की आपत्तियों से भी ज्यादा चौंकाने वाली है, इस संदर्भ में अमेरिका की प्रतिक्रिया। अमेरिका ने इज़रायल को साफ कह दिया, उसकी आपत्तियों के बावजूद वह कतर व टर्की को बोर्ड का सदस्य बनाएगा, क्योंकि उस पर (अमेरिका पर) भारी अन्तर्राष्ट्रीय दबाव है, कि “गाज़ा स्ट्रिप” के पुनर्निर्माण को आगे बढ़ाये।

■ अमेरिका की प्रतिक्रिया ने अन्तर्राष्ट्रीय “डिप्लोमैसी” (कूटनीति में) उसका सोच उजागर कर दिया है कि वह तत्कालिक लाभ (ट्रांज़ैक्शनल अप्रोच) के पक्ष में हैं, न कि दूरगामी मित्रता व नजदीकियों में।

■ यह सोच बहुत चौंकाने वाला तो है ही इसने अन्य देशों को भी चौंकसा कर दिया है, अमेरिका के वादों के प्रति।

दरारें उजागर हुई हैं, बल्कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के तहत अमेरिका के गठबंधनों को लेकर व्यापक सोच भी सामने आई है। इस विवाद के केन्द्र में युद्ध के बाद गाज़ा के प्रशासन के लिए वॉशिंगटन

द्वारा हाल ही में प्रस्तुत ढांचा है। इस प्रस्ताव में एक निगरानी बोर्ड शामिल है, जिसके पास पुनर्निर्माण, सुरक्षा समन्वय और नागरिक शासन की ज़िम्मेदारी संचालने वाला एक शक्तिशाली कार्यकारी अंग होगा। महत्वपूर्ण बात यह

है कि इस कार्यकारी निकाय में क्रतर और तुर्की को शामिल किया गया है-दो ऐसे देश जिन पर इज़रायल गहवा संदेह करता है। इज़रायल लंबे समय से क्रतर पर हमास से संबंध रखने का आरोप लगाता रहा है, जबकि राष्ट्रपति तैयप

एर्दोआन के नेतृत्व में तुर्की गाज़ा युद्ध शुरू होने के बाद से नेतन्याहू के सबसे मुखर आलोचकों में शामिल रहा है।

इज़रायल की प्रतिक्रिया त्वरित और तीखी रही। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इस योजना पर इज़रायल से

कोई समन्वय नहीं किया गया और यह “इज़रायल की घोषित नीतिगत प्राथमिकताओं के सीधे खिलाफ है”, विशेषकर युद्ध के बाद गाज़ा में शत्रुतापूर्ण क्षेत्रीय शक्तियों के प्रभाव को रोकने के उसके लक्ष्य के संदर्भ में। इज़रायल के लिए क्रतर और तुर्की की भागीदारी कोई तकनीकी विवरण नहीं, बल्कि एक खतरे की रेखा है-क्योंकि यह उस युद्धोत्तर ढांचे का संकेत देती है जिसे इज़रायल उन ताकतों द्वारा आकार दिया हुआ मानता है जो हमास-समर्थित नेटवर्क को निष्प्रभावी करने के बजाय वैधता प्रदान करेंगी। हालांकि, लोगों को इज़रायल की अस्वीकृति से नहीं, बल्कि वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया से भी हैरानी हुई है। वरिष्ठ (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## वर्षा के बाद भी दिल्ली में प्रदूषण नहीं घटा

नयी दिल्ली, 24 जनवरी। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को हुई बारिश और तापमान में गिरावट के बावजूद शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब श्रेणी में बनी रही।

■ शहर के कुछ इलाकों में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में रहा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शहर के कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर अब भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है।

सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार सुबह दिल्ली का औसत एक्यूआई खराब श्रेणी में रहा, जिसमें सूक्ष्म कणों (पीएम 2.5) की अधिकता देखी गई।

विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के कारण तापमान में तो कमी आई है लेकिन प्रदूषण के स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## गणतंत्र दिवस परेड: पहली बार दो विदेशी नेता चीफ गैस्ट होंगे

- जाल खंबाता -  
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -  
नई दिल्ली, 24 जनवरी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फ़ॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतेनियो

■ भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बतौर चीफ गैस्ट यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउन्सिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को आमंत्रित किया है।

कोस्टा 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली भारत की 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर )